www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 38 अंक 47 पृष्ठ 40 | नई दिल्ली 22-28 फरवरी 2014 | ₹ 8.00

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोज़गार परिदृश्य

नीता निराश

रोज़गार से सबसे पहले आर्थिक रूप से सुरक्षित होने की खुशी का अहसास होता है. लेकिन इच्छानुसार रोज़गार मिलना हमेशा आसान नहीं होता और खासकर जब कोई ऐसे क्षेत्र का निवासी हो जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है और लगभग पूरी तर भूमिगत जल पर निर्भर हो, जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हो या वो क्षेत्र उग्रवादियों से प्रभावित हो. सिक्किम को मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य हैं-असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा. इसका भू-क्षेत्र 2,62,179 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 45.5 मिलियन लोग ही रहते हैं. भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.9 प्रतिशत यह क्षेत्र अब भी पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में है. 1947 में देश के विभाजन के बाद से अपनी चमक खो चुके इस क्षेत्र को फिर से प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. यह क्षेत्र भौगोलिक और राजनीतिक रूप से कटा हुआ है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में साक्षरता के मानक राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं. वहां के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अब रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. बाज़ार की प्रतिस्पर्धा के अनुसार उन्हें तैयार करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, व्यावसायिक शिक्षा, भाषा, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (2001) की स्थापना की थी जिसे मंत्रालय बना दिया गया (2004). पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति घनत्व काफी कम है. संसाधनों के ज्यादा इस्तेमाल न होने के कारण क्षेत्र में विकास संबंधी प्रक्रियाओं को गति नहीं मिल पाती. राज्यों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएं हैं. लेकिन अब हर तरह से आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की सलाह के अनुसार ढांचागत विकास तथा कनेक्टिविटी सुधारने संबंधी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं. यहां कृषि, रोज़गार का मुख्य साधन है. सभी 8 राज्यों की सरकारें अब तक रोज़गार के अधिकांश अवसर उपलब्ध करा रही हैं. नियोजनीय युवाओं की कमी के कारण, रोज़गार परिदृश्य थोड़ा फीका है. सिक्किम को छोड़कर कुछ राज्यों में उग्रवाद की समस्या भी एक वजह है. वहां युवा, कार्यालयों में बैठ कर काम करना पसंद करते हैं और उद्यमिता में बहुत कम रुचि रखते हैं.

इसे भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय के रोज़गार और बेरोज़गार सर्वेक्षण 2009-10 से सबसे अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है. (मुख्य उद्योग समूह में नियुक्त प्रति 1000 व्यक्तियों पर नियमित मज़दूरी/वेतन भोगियों के वितरण संबंधी आंकड़े). असम में 219 व्यक्ति कृषि, वानिकी में थे, खनन और उत्खनन में 16, विनिर्माण में 69, बिजली में 25, निर्माण में 9, थोक और खुदरा क्षेत्र में 22, परिवहन-भंडारण में 83, वित्तीय और बीमा में 22, सामुदायिक सेवाओं में 248 तथा अन्य में 248 व्यक्ति थे. मेघालय में कृषि में 291, खनन और उत्खनन में 28, विनिर्माण में 0, बिजली में 5, निर्माण में 2, थोक और खुदरा क्षेत्र में 26, परिवहन-भंडारण में 60, वित्तीय और बीमा में 0, सामुदायिक सेवाओं में 348 तथा अन्य सेवाओं में 240 व्यक्ति हैं. जबकि सिक्किम में कृषि और वानिकी में 37, खनन में 0, विनिर्माण में 586, बिजली में 3, निर्माण , थोक और खुदरा क्षेत्र, परिवहन-भंडारण में 0, सामुदायिक सेवाओं में 10 तथा अन्य सेवाओं में 364 व्यक्ति हैं.

राज्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं. मनरेगा का उद्देश्य गरीब लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना है जो कि उनके लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है. ग्रामीण आबादी को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराने में मणिपुर, नगालैंड और सिक्किम क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. बागवानी में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या काफी अधिक है. सिविल सेवा के लिए कोचिंग से अधिक पूर्वोत्तर युवाओं को सरकार में देख सकते हैं हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकांश राज्यों में विकास और गिरावट के रुझानों का एक ही कारण है और लगभग एक ही जैसी चुनौतियां हैं तथा अगर कुछ जगहों पर रोज़गार की स्थिति देखें तो वो भी एक ही जैसी लगेंगी.

2011 की जनगणना के अनुसार असम की जनसंख्या 3,1169272 थी जिसमें 1,5954927 पुरुष और 15214345 महिलाएं थीं. उस हिसाब से कारखानों, छोटे उद्योग, चाय और रबड़ के उद्योगों की संख्या बढ़ाने के साथ रोज़गार का सृजन किया जा रहा है. मझौले और लघु उद्योगों ने 2010.11 तक 178054 व्यक्तियों को रोज़गार दिया. कारखानों की संख्या बढ़ाई गई तथा 150485 व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान किया गया. चाय उद्योग राज्य में 6 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान कर रहा है जो कि देश में हर रोज़ मज़दूरों के रोज़गार की कुल औसत संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत है. रबड़ उत्पादन से 2010-11 में 276750 लोगों को दिहाड़ी पर काम मिला. रेशम उत्पादन से 2.5 लाख से अधिक परिवारों को रोज़गार मिला. यह एक प्रमुख कुटीर उद्योग है. (आर्थिक सर्वेक्षण असम 2011-12)

(शेष पृष्ठ 39 पर)

रोज़गार सारांश

रेलवे

- पूर्व मध्य रेलवे को 422 फिटर, मशीनिष्ट, टर्नर आदि की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 14.03.2014

भारतीय स्टेट बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक को 393 विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 06.03.2014

म.को.लि.

- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को 160 माइनिंग सिरदार और उप सर्वेयर की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 07.03.2014

सें.को.लि.

- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पैरा मेडिकल स्टाफ के 116 पदों पर भर्ती

अंतिम तिथि: 02.03.2014

गेल

- गेल (इंडिया) लिमिटेड को 12 प्रबंधक, उप प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 04.03.2014

सं.लो.से.आ.

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

अंतिम तिथि: 13.03.2014

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड के तहत निम्नलिखित आलेख उपलब्ध हैः-

1. अंतरिम रेलवे बजट 2014-2015

पशुपालन और पशुधन क्षेत्र में रोज़गार के अवसर

डॉ. अरुण एस. निनावे

पशुपालन के क्षेत्र में रोज़गार सृजन की अपार संभावनाएं हैं. डेरी उद्योग, भेड़ पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन और सूअर पालन के क्षेत्र में बेरोज़गार युवाओं के लिए स्वरोज़गार के उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध होते हैं. प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ रही ग़रीबी को कम करने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका भारत के कुल कृषि उत्पाद मूल्य में करीब 26 प्रतिशत का योगदान है. दूध, मांस और कुक्कुट उत्पादों के जरिए पशुधन उत्पादों का निर्यात प्रति वर्ष करीब 42.25 अरब रुपये का है. यह दूध, मांस, अंडों के जरिए उत्कृष्ट प्रोटीन उपलब्ध करवाने के अलावा, कृषि के लिए उर्वरा शक्ति और खाद भी उपलब्ध करवाता है. इस क्षेत्र में निवेश के लिए भी बहुत अच्छी संभावना है और पशु पालन के क्षेत्र में निवेश से प्रति वर्ष 30-35 प्रतिशत का आसानी से रिटर्न मिल जाता है.

पशुधन व्यापक रूप से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है और इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में अपना महत्व स्थापित कर लिया है. ग़रीबी उन्मूलन के औज़ार के तौर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं. यह क्षेत्र न केवल किसानों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत है बल्कि एक ओर जहां लाभदायक रोज़गार उपलब्ध करवाता है, साथ ही व्यक्तियों की महत्वपूर्ण और विभिन्न पोषक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है. ये एजेंसियां पशुधन और कुक्कुट के बेहतर उत्पादों के संपूर्ण सुधार के लिए व्यवहार्य गतिविधियों की संभावना, अनुकूलन, संचालन, प्रोत्साहन, आयोजन के मिशन के तौर पर काम करती हैं जिससे किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए लाभदायक स्वरोज़गार सृजन हो सके.

पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय पर पशुधन उत्पादन, संरक्षण और रोगों से परिरक्षण तथा पशुओं के सुधार तथा डेरी विकास से संबंधित मामलों का दायित्व है. डेरी विकास दुग्ध उत्पादन को एक सहायक व्यवसाय के तौर पर उपलब्ध करवाते हुए ग्रामीण खेतिहर समुदाय के बीच सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ एक औज़ार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. यह लोगों के पोषक मानदंड को सुधारने में भी मददगार होता है. राज्य स्तर पर पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक (कुक्कुट); कुक्कुट विकास और विपणन के प्रभारी; संयुक्त निदेशक (फार्म्स); मवेशी विकास के प्रभारी और संयुक्त निदेशक (पशु प्रजनन); वेक्सीन उत्पादन; पशु देखभाल और रोग निदान के प्रभारी की सहायता से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये मण्डल स्तरीय अधिकारियों से युक्त होता है. ये अधिकारी उप निदेशकों के रैंक के सभी पशुपालन अधिकारियों को तकनीकी साधन उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनके सहयोग के लिए विषय मामला विशेषज्ञ अर्थात पशुधन विकास अधिकारी/खण्ड पशुचिकित्सा अधिकारी, मवेशी विकास, कुक्कुट विकास अधिकारी, रोग निदान आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए रोग अन्वेषण अधिकारी, अधीक्षक जिला पशु चिकित्सा अस्पताल, प्रबंधक अंडज उत्पत्तिशाला आदि होते हैं. इन पदों के समर्थन में क्षेत्रीय स्तर के संस्थान जैसे कि अस्पताल, औषधालय, ए.आई. सेंटर, कुक्कुट विस्तार केंद्र, चलते फिरते औषधालय, खच्चर प्रजनन केंद्र, कुक्कुट प्रदर्शन केंद्र, अंडज उत्पत्तिशाला आदि होते हैं. मवेशी प्रजनन फार्मों और पशुचिकित्सा अस्पतालों की सहायता के लिये सहायक पशुचिकित्सा सर्जन, अन्य अर्द्ध पशुचिकित्सा कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी रखे जाते हैं.

पशु चिकित्सा विज्ञान में कॅरिअर

पशुचिकित्सा विज्ञान पक्षियों और पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के निदान, इलाज और उपचार का विज्ञान है. एक पशुचिकित्सा विज्ञानी की प्रमुख ज़िम्मेदारी पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करना होता है. ज़्यादातर पशुचिकित्सा विज्ञानी कुत्तों, बिल्लियों या अन्य घरेलू जानवरों की देखभाल करते हैं जबकि कुछ पशुचिकित्सा विज्ञानी बड़ी-बड़ी बिल्लियों और प्राणी उद्यानों के अन्य पशुओं का इलाज करते हैं. इलाज करने के अलावा पशुचिकित्सक समय पर टीकाकरण और दवाइयां देकर पशुओं में बीमारियां फैलने से रोकते हैं और पशु-पक्षियों में विभिन्न प्रकार के रोगों से निपटने के बारे में परामर्श देते हैं. एक पशुचिकित्सक की मुख्य ज़िम्मेदारी पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और कल्याण होती है. अधिकतर पशुचिकित्सक कुत्तों, बिल्लियों या अन्य घरेलू पशुओं की देखरेख करते हैं जबकि कुछ जंगली जानवरों, जैसे कि प्राणी उद्यानों में रखे जाने वाली बिल्लियों और अन्य पशुओं का इलाज करते हैं. इलाज करने के अलावा पशुचिकित्सक पशुओं में बीमारियां फैलने से रोकने के लिए समय पर उनकी सर्जरी और टीकाकरण तथा चिकित्सा भी करते हैं और पालतु पशुओं और फार्म पशुओं की देखभाल पर परामर्श देते हैं. उनकी गतिविधियों में पशुपालन-चयन प्रजनन से पशु प्रजनन में सुधार और कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के जरिए

(शेष पृष्ठ 40 पर)

सिविल सेवा परीक्षा-अवसरों की संख्या में छूट

सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट के साथ संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये दो अतिरिक्त अवसर मिलेंगे. केंद्रीय सरकार ने सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा 2014 से, सभी श्रेणियों के लिये अधिकतम आयु की आनुषंगिक आयु छूट के साथ, यदि अपेक्षित है, दो अतिरिक्त अवसरों का अनुमोदन कर दिया है.

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 22/24.02.2014 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 20.02.2014

पशुपालन और पशुधन...

(पृष्ठ 1 का शेष)

पारेषित होने वाली बीमारियों के फैलने पर नियंत्रण के वास्ते पशु अनुसंधान भी शामिल हो सकता है. उनके कार्य में वन्यजीव संरक्षण, कुक्कुट प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल होता है. पशुओं से गहरा लगाव पशुचिकित्सक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उन्हें तैयार और सुखदायी बना सकता है. पशुपालन के तहत व्यापक रूप में विभिन्न प्रकार के रोज़गार आते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं की देखभाल और प्रजनन पर फ़ोकस रहता है. इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों में पशुधन, डेरी और कुक्कुट पालक शामिल हैं. इन पेशेवरों पर फार्म में पशुओं के प्रजनन, विपणन और देखभाल की ज़िम्मेदारी होती है. रोज़मर्रा से जुड़े कार्यों में पशुओं को चारा देना, गौशाला और बाड़े की साफ-सफाई करना, जन्म क्रिया के समय पशुओं की सहायता करना और उपकरणों का रखरखाव करना शामिल होता है. पशुपालन से जुड़े पेशेवर या तो स्वयं कार्य संपन्न करते हैं अथवा दूसरे कामगारों के कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं जो कि फार्म के आकार पर निर्भर करता है. पशुओं की देखभाल करने के अलावा पशुपालन विशेषज्ञ अकसर अपने वार्ड्स के लिए सुविधाओं के रखरखाव और अनुरक्षण में सहायता करते हैं. एक पशुपालन विशेषज्ञ बनने के लिए अनुसंधान, शिक्षण और कौशल संबंधी अपेक्षाओं का होना ज़रूरी होता है.

शैक्षणिक अपेक्षाएं

पशुपालन पेशेवर बनने के इच्छुक व्यक्ति एक एसोसिएट डिग्री कार्यक्रम के रूप में औपचारिक शिक्षण अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने का विकल्प चुन सकते हैं. पशुपालन पेशेवर हाई स्कूल डिप्लोमा धारण करते हैं, कई लोगों ने फार्म मैनेज़मेंट अथवा अन्य संबंधित क्षेत्रों में किसी कृषि विद्यालय से डिग्रियां अर्जित की होती हैं. फार्म मैनेज़मेंट डिग्री कार्यक्रमों में तकनीकी फार्म प्रशिक्षण के साथ-साथ अर्थशास्त्र, विपणन और पर्यावरण में पाठ्यक्रम शामिल होते हैं. इस प्रवृत्ति के अलावा कई फार्म व्यावसायिक पहले से अनुभव प्राप्त पशुपालन पेशेवरों द्वारा कार्य के साथ-साथ प्रशिक्षित किये जाते हैं अथवा अपने संपूर्ण जीवन में फार्म में रहते हुए अनुभव प्राप्त कर लेते हैं.

चिकित्सा की तरह, पशुचिकित्सा विज्ञान का अध्ययन भी 10+2 के उपरांत किया जा सकता है जिसके लिये मौलिक अपेक्षा 10+2 में भौतिकी, रसायनशास्त्र और जीवविज्ञान का संयोजन है. लगभग सभी राज्यों में स्थित पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं. अध्ययन का स्नातक पाठ्यक्रम चार वर्ष की अवधि के लिये होता है, जिसके उपरांत एक वर्ष की व्यावहारिक इंटर्नशिप होती है. यह पाठ्यक्रम बी.वी.एससी के तौर पर जाना जाता है और दूसरे विषय क्षेत्रों की तरह इसमें मास्टर पाठ्यक्रम का अध्ययन भी किया जा सकता है. मास्टर पाठ्यक्रम एम.वी.एससी के तौर पर जाना जाता है. मास्टर पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन की विशेषीकृत शाखा की आवश्यकता होती है. इसके तहत नियमित चिकित्सा क्षेत्र की तरह मेडिसिन, सर्जरी, गाइनेकोलॉजी, पैथोलॉजी, पशु उत्पादन और इसी तरह के अन्य नियमित पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं. अधिक विशिष्ट विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों के लिये एनिमल एनॉटमी, पशु जैवचिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, पशु अर्थव्यवस्था, पशुपालन विस्तार, पशु प्रजनन, पशुधन विस्तार, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन, डेरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डेरी कैमिस्ट्री, डेरी इंजीनियरिंग, डेरी माइक्रोबायोलॉजी, खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान, खाद्य एवं चारा प्रौद्योगिकी, पशु पोषण, कुक्कुट विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूअरपालन, प्रिवेंटिव मेडिसिन और टोक्सिकोलॉजी आदि कई नामों से पाठ्यक्रम हैं.

ज़्यादातर पशुचिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रदान किया जाता है. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में बैचलर (बीवीएससी एंड एएच) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 'अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एआईसीईई) का आयोजन करती है. बीवीएससी एंड एएच की अवधि इंटर्नशिप की अवधि सहित साढ़े चार से लेकर पांच वर्ष तक की होती है. मास्टर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) द्वारा एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है.

रोज़गार की संभावनाएं

पशुचिकित्सा विज्ञानी सरकारी पशुपालन विभागों, कुक्कुट उत्पादन केंद्रों, डेरी उत्पादन केंद्रों, भेड़ और खरगोश पालन केंद्रों, निजी और सरकारी पशुचिकित्सा अस्पतालों और क्लीनिकों में कार्य करने का व्यवसाय चुन सकते हैं. डेरी अनुसंधान संस्थानों में भी पशुचिकित्सकों की सेवाओं की आवश्यकता होती है. शहरी क्षेत्रों में पशुचिकित्सा विशेषज्ञों की निजी प्रेक्टिस भी काफी पनप सकती है. सरकार पशुचिकित्सकों को जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के तौर पर भी नियुक्त करती है जिनकी सेवाएं प्राणी उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में ली जाती हैं. रक्षा सेनाएं घोड़ों, कुत्तों, ऊंटों आदि का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें भी पशुचिकित्सकों की आवश्यकता होती है. विभिन्न प्राणीविज्ञान अनुसंधान संस्थान विभिन्न विभागों में अनुसंधान और विकास कार्य संचालित करने के लिए पशुचिकित्सा विज्ञानियों को नियुक्त करते हैं. पशुचिकित्सा विज्ञानी शिक्षण संकाय के तौर पर अकादमिक संस्थानों में भी कार्य ग्रहण कर सकते हैं. पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर आगे इसी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने का व्यवसाय चुन सकते हैं. सर्वोच्च कालेज स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर/अन्य पाठ्यक्रम संचालित करते हैं. कई तकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय भी पशुचिकित्सा विज्ञानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं.

भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पांच वर्षीय कार्यक्रम बीवीएससी (पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में बैचलर) पूरा करने के उपरांत कोई व्यक्ति चिकित्सा, सर्जरी, बायोकैमिस्ट्री, आनुवंशिकी और प्रजनन, कुक्कुट विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इम्युनोलॉजी आदि जैसे किसी भी एक क्षेत्र में मास्टर स्तर पर स्नातकोत्तर के दौरान विशेषज्ञता का विकल्प दे सकते हैं. एमवीएससी के उपरांत कोई व्यक्ति भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान अथवा राज्य विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अनुसंधान अथवा शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर सकता है. ये संस्थान और दूसरे अत्याधुनिक तथा उत्कृष्ट संस्थान पशुधन क्षेत्र में अभिनव परियोजनाओं जैसे कि एसपीएफ अंडों का उत्पादन, पशु स्वास्थ्य उत्पाद, पशु वेक्सीन इकाइयां, फीड प्लांटस, बूचड़खाने, एकीकृत कुक्कुट एवं सूअर परियोजनाओं आदि पर विशेष ज़ोर दे रहे हैं. अवसंरचना परियोजनाएं जैसे कि पशुचिकित्सा संस्थान, वेक्सीन उत्पादन केंद्र आदि पशुपालन क्षेत्र में काफी मात्रा में रोज़गार के अवसरों का सृजन कर सकती हैं. पशुचिकित्सा विज्ञानों के क्षेत्र को बेहतर फ़ोकस प्रदान करने और पशुचिकित्सा, डेरी और मात्स्यिकी क्षेत्र को शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार में अधिक अर्थपूर्ण बनाने के वास्ते संस्थान और कॉलेज राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से इन संस्थानों/कॉलेनों को अलग करते हुए राज्य पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में स्थापित किये जा रहे हैं. शिक्षा, अवसंरचना समर्थन और गुणवत्ता मानकीकरण भी भा.कृ.अ.प. और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से समर्थित और परीक्षित होता है.

पारिश्रमिक

पशुचिकित्सकों का पारिश्रमिक उनके कार्य और उनके अधीन इलाज से संबंधित आने वाले पशुओं के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है. सरकारी पशुचिकित्सा केंद्रों/अस्पतालों में नव-स्नातकों को कनिष्ठ पशुचिकित्सा सर्जन के तौर पर नियुक्त किया जाता है. उनका शुरूआती वेतनमान रु. 20,000 से रु. 25,000 प्रतिमाह के बीच होता है. एक निजी चिकित्सक अपने अनुभव और लोकप्रियता के अनुसार महत्वपूर्ण आय अर्जित कर सकता है. वह प्रति रोगी रु. 100-500 तक अर्जित कर सकता है जो कि पशु के इलाज की प्रकृति पर निर्भर करता है. एक सहायक प्रोफेसर के तौर पर पशुचिकित्सा विज्ञानी वरिष्ठ स्तर के पद पर रु. 25000/- से लेकर रु. 35000/- तक वेतन अर्जित कर सकता है.

पशुचिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पारिश्रमिक के साथ अनुसंधान कार्य कर सकते हैं. एक पशुचिकित्सक औसतन रु. 15000/- से रु. 50000/- प्रतिमाह की रेंज में अर्जित कर सकता है. प्रेक्टिस की प्रकृति से पारिश्रमिक की राशि का निर्धारण होता है. सामान्यतः निजी चिकित्सक आकर्षक पारिश्रमिक अर्जित करता है. यद्यपि इस व्यवसाय में चिकित्सा व्यवसाय की तरह बेहतर संतुष्टि किसी का दर्द दूर करने से ही प्राप्त होती है. इसमें संतुष्टि कुछ हद तक अधिक होती है क्योंकि इसमें बेजुबान पशु शामिल होते हैं.

निजी क्षेत्र में, वेतन अनुभव, पदनाम और कार्यनिष्पादन के अनुसार बढ़ता जाता है. सेल्स और मार्केटिंग में पैसा अधिक है लेकिन कार्यनिष्पादन का महत्व ज्ञान से अधिक होता है. एक प्रबंधक के तौर पर कोई व्यक्ति अन्य सेल्स व्यावसायिकों की तरह कार्य कर सकता है. निजी प्रेक्टिस में आमदनी पूरी तरह ग्राहकों पर निर्भर करती है. खुशहाल इलाके में जहां पर पालतू जानवरों के क्लीनिक भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले दोगुना होते हैं, ग्राहक 30-40 मिनट के काम के लिये हजारों रुपये का भुगतान कर सकता है. ग्रामीण क्षेत्र में पशुचिकित्सा विज्ञानियों के लिए रोज़गार के बहुत से विकल्प होते हैं. डेरी और कुक्कुट उत्पादन केंद्र को पशुचिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है. इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं-दुग्ध, अंडा और अन्य उत्पादों का उत्पाद. कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्पादन केंद्र पर रखे जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी भी पशुचिकित्सा विशेषज्ञों की होती है. सरकार पशुचिकित्सा विज्ञानियों को जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के तौर पर भी नियुक्त करती है जिनकी सेवाएं प्राणी उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में प्रयोग में लाई जाती हैं. रक्षा सेनाएं घोड़ों, कुत्तों, ऊंटों आदि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करती हैं और उन्हें भी पशुचिकित्सा विज्ञानियों की आवश्यकता होती है. विभिन्न संगठन पशुचिकित्सा विज्ञानियों को शिक्षण क्षेत्र सहित अपने अनुसंधान और विकास विभागों में नियुक्त करते हैं. पशुचिकित्सा विज्ञानियों के लिये सरकारी नौकरियों, गैर सरकारी संगठनों और दूसरे कार्यक्रमों में रोज़गारों के अलावा निजी क्षेत्र में सेल्स आदि में भी काफी संभावनाएं हैं. योग्य चिकित्सकों को समुचित राशि का भुगतान किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और पशुधन विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोज़गार के विकल्प मौजूद हैं.

सांकेतिक संस्थान और विश्वविद्यालय

1. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज़्ज़तनगर, उत्तर प्रदेश. http://www.ivri.nic.in
2. महाराष्ट्र पशु और मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय (एमएईएसयू), नागपुर, महाराष्ट्रः http://www.mafsu.in
3. कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु और मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर, कर्नाटक http://www.kvafsu.kar.nic.in
4. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार http://hau.ernet.in.clink/covs.html
5. बम्बई पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय www.mafsu.in/bvc/bvcollege/bvc_main_page.html
6. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय (आणंद कृषि विश्वविद्यालय), आणंद http://aau.in/?q=college-menu/702
7. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर http//www.jnkvv.nic.in
8. चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय www.csauk.ac.in
9. पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरिनॅरी एंड एनिमल सांइसेस, अकोला http://www.pgivasakola.in
10. कॉलेज ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस, उदगिर, महाराष्ट्र www.mafsu.in/udgir/udgri main.html
11. गुरु अंगद देव वेटरिनॅरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, लुधियाना www.gadvasu.in
12. आल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता http://www.aiihph.gov.in

(लेखक वर्तमान में जैवप्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में वैज्ञानिक ''जी'' और सलाहकार के तौर पर कार्यरत हैं.
ई-मेल : ninawe@gmail.com)

रोज़गार समाचार

श्रुति पाटील
महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
डॉ. ममता रानी
संपादक
नलिनी रानी
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)
इरशाद अली
(संपादक वितरण)
विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार
केपी मणिलाल
लेखा अधिकारी

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल-महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
director.employmentnews@gmail.com
विज्ञापन : enewsadvt@yahoo.com

संपादकीय :	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सा विज्ञान संस्थान
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ. प्र.) भारत
फोन नं. 0522-4918555, 504, फैक्स 0522-4918506
वेबसाइट : www.drrmlims.ac.in

विज्ञापन सं.
35/आरएमएलआईएमएस/2014/डायरेक्टर कैम्प

संशोधन/शुद्धिपत्र

भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग में संकाय/गैर संकाय रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन संख्या 13/आरएमएलआईएमएस/2014/डायरेक्टर कैम्प दिनांक 18.01.2014 के संदर्भ में, भौतिक चिकित्सक और व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञानी के पद के लिए अनिवार्य योग्यता में संशोधन किया जा रहा है. विवरणों के लिए कृपया वेबसाइट **www.drrmlims.ac.in** पधारें.
निदेशक
रो.स. 47/60

सफल उद्यमी बनें

- नि:शक्तजनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को 100% अनुदान
- 1,000/- प्रति व्यक्ति प्रतिमाह वजीफा भी
- वेबसाइट **www.nhfdc.nic.in** पर ऑनलाइन आवेदन करें

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007
दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371
ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in
रो.स. 47/92

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए **ईरा जोशी,** अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादकः डॉ. ममता रानी